

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 24 / 2013 / बाड़मेर
2. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 25 / 2013 / बाड़मेर
3. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 26 / 2013 / बाड़मेर
4. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 27 / 2013 / बाड़मेर
5. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 28 / 2013 / बाड़मेर
6. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2013 / बाड़मेर
7. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 30 / 2013 / बाड़मेर
8. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2013 / बाड़मेर
9. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 33 / 2013 / बाड़मेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, बाड़मेर  
बनाम

अपीलार्थी सभी प्रकरणों में (अप्रार्थी)

1. मनीधरी ग्वारगम इण्ड., बाड़मेर
2. गौतम गम एण्ड कैमिकल्स मिल्स, बाड़मेर
3. अरिहन्त इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर
4. महावीर ग्वारगम उद्योग, बाड़मेर
5. आर.के. ग्वारगम उद्योग, बाड़मेर
6. मेहता ग्वारगम उद्योग, बाड़मेर
7. महालक्ष्मी गम इण्ड., बाड़मेर
8. सूरजदाल मिल, बाड़मेर
9. प्रकाश ग्वारगम उद्योग, बाड़मेर

प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-24 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-25 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-26 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-27 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-28 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-29 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-30 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-32 / 2013) (प्रार्थी)  
प्रत्यर्थी (प्रार्थना पत्र संख्या-33 / 2013) (प्रार्थी)  
.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.आर.सिंघवी  
अभिभाषक  
श्री डी.पी.ओझा  
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

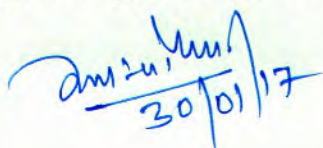
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.17

निर्णय

ये दस संशोधन पत्र अपीलार्थी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 282/2011/बाड़मेर से 290/2011/बाड़मेर में पारित पृथक-पृथक निर्णय 30.11.2012 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त सभी संशोधन प्रार्थना पत्र में निर्णय हेतु बिंदु समान निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक पत्रावलियों रखी जा रही है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि respondent assessee is engaged in business of manufacturing Gwar gum, Gwar split, Churi Korma , etc., from Gwar dal. The Assessing Officer, while making assessment for year 2006-07, found out that the respondent assessee had paid VAT on the purchases of Gwar as raw material, in order to manufacture from it Gwar gum ,Gwar split which were Taxable commodities and Churma Kori which

  
30/11/17



लगातार.....2



was a tax exempt commodity. While allowing claim for input tax credit on manufacturing and sale of Gwar gum proportionately, the Assessing Officer disallowed the assessee's claim of input tax credit on sale of 'Churi Korma' - a commodity exempt from tax-proportionately and reversed it. It also charged interest on the input tax credit reversed.

Aggrieved by the order of Assessing Officer, the respondent assessee preferred an appeal before the Appellate Authority who decided that gwar purchased from registered dealers was essentially used in manufacture of gwar gum ;and, in the process of manufacture, Churi Korma was obtained as bye product which was no doubt a tax exempt commodity, but Gwar was purchased with main aim of manufacturing 'Gwar gum' from it and not 'Churi Korma' ; and ,reversal of input tax credit on sale of Churi Korma proportionately was wrongly effected by Assessing Officer.

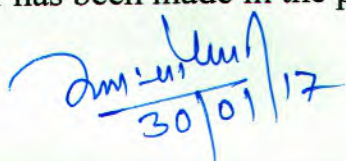
The Appellate Authority, relying on the judgment of the Board in case of Commercial Taxes Officer (Anti Evasion), Sri Ganganagar reported in (2009) 28 tax update 360, set aside the aforesaid assessment order of Assessing Officer.

Being aggrieved by the order of the Appellate Authority, this appeal has been filed by the Revenue before the Board. The contention of the Revenue is that the Assessing Officer was within law in reversing input tax credit proportionately on the sale of 'Churi Korma'.

कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण के उक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलों का निस्तारण 30.11.2012 को करते हुये अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करते हुये कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत रखा है जिनमें संशोधन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र व्यवहारियों की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं।

संशोधन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना पत्र के आधारों में निम्न कथन किया है :-

That the finding in the middle para at page no. 5 the impugned order date 30-11-2012 that an analysis of the present case in the light of aforesaid judgement of the hon'ble Raj. high court reveals that in instant case input tax credit was also allowed proportionately to the extent mfg. and sale of taxable goods i.e. Gwar gum etc. it manufactured out of VAT paid Gwar (raw material) and disallowed to the extent of manufacture and sale of Gwar churi proportionately which is in conformity with the aforesaid judgement of the Hon'ble H.C. ", is quite erroneous and contrary to the facts on record because no propionate allowance or disallowance of the ITC on VAT paid Gwar has been made in the present case, which is the legal mandate as per

  
30/01/17





the judgment of hon'ble H.C. supra as well as the judgment and order date 05-12-2012 passed by the another D.B. of this hon'ble board (35 TAX UPDATE PAGE 13) where as in the present case, the learned assessing officer had estimated the value of raw material used in the manufacturing of Gwar churi by making of certain deduction in the sale value of Gwar Churi which resulted in the reversal of tax at the amount of more than ITC, which in no way can be held as "proportaintely" in conformity with the judgment of Hon'ble H.C."

That the findings recorded in the para below there produced statutory provisions of section 18 of the RVAT Act 2003 at page 3 of the impugned order date 30-11-2012 in respect of the Revenue arguments, are also erroneous and contrary to the actual facts, because the revenue has taken a ground in its appeal itself that the facts of the case of appellant are distinguishable with the facts of the case of M/s Durgeshwari Food Ltd. in as much as in the course of hearing it has duly has been conceded by the D.R. taht the reversal of Tax more tahn ITC is a glaring mistake on the part of the assessing officer and the absence of the findings learned Dy. comm. (Appeals) on all the grounds raised by the assessee, would entail the remanding of case back, either to DC(Appeal) or to the assessing officer as may be deemed proper by the Hon'ble bench. In this view of the matter, there can be no occasion to record the finding of Revenue's arguments that "He vehemently opposed the respondent assessee raising new issues like the assessing officer not addressing the large opening stock of Gwar churi etc. and the appellate authority not redressing such factual matters, which in his view was a device used by the respondent to circumvent the legal issue of disallowance of input tax credit on manufacture and sale of Gwar Churi proportionately at the backdrop of the aforesaid judgment."

उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 30.11.2012 में रेकार्ड से परिलक्षित भूल होने से संशोधनीय है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2012 को विधिक बताते हुये कथन किया कि संशोधित आधारों में ऐसी किसी भूल को इंगित नहीं किया गया है जो भूल रेकार्ड से परिलक्षित होती हो। उन्होंने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत तर्कों एवं की गई बहस पर विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय दिनांक 30.11.2012 पारित किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्रों पर जिस बिन्दु को उठाया गया है, उस पर बिन्दु को अपील सुनवाई के दौरान भी उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही माननीय खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 30.11.2012 पारित किया गया है, इसलिए उक्त निर्णय



संशोधन योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो बिना वाद-विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित भूल प्रकट होती है। निर्णय दिनांक 30.11.2012 में ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत किया।

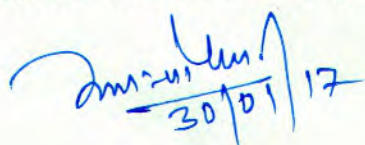
उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2012 पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर निर्णय दिनांक 30.11.2012 में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है, उन्हीं बिन्दुओं को अपील की बहस के दौरान उठाया गया है, जिन पर विचार करने के पश्चात ही खण्डपीठ द्वारा निर्णय पारित किया है। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो भूल रिकार्ड से परिलक्षित होती हो। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरते हैं।

बहस के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Ms Durgeshwari Food Industry Ltd., Sri Ganganagar, reported in (2012)32 Tax update 03 के प्रकरण में प्रतिपादित मत को उद्धरित करते हुये विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलों का निस्तारण किया है जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

“In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, “Atta”, “Maida” and “Suji”, manufactured of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the

लगातार.....5

  
30/01/17



revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

बहस के दौरान विभागीय पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

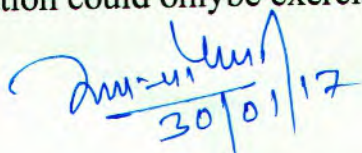
“The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

“The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf.”

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held that such a power of rectification could only be exercised when there is an error apparent on the

  
30/01/17

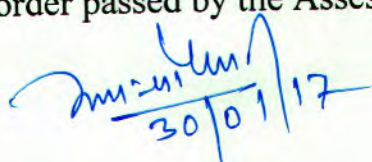




face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification / modification / correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

लगातार.....7

  
30/01/17



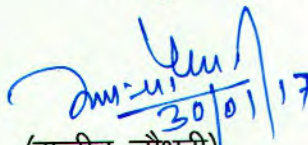


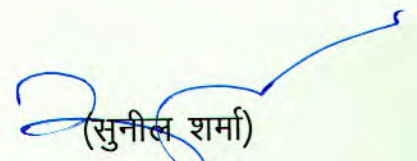
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।

माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलों की बहस के दौरान उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात निर्णय दिनांक 30.11.2012 पारित किया गया है जिसमें कोई भी भूल रेकार्ड से परिलक्षित नहीं होती है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में मत प्रतिपादित के आलोक में व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होन से अस्वीकार किये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य